Media interaction after power sector review of West Bengal

22.08.2016, Kolkata

आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय श्री मनीष दा के साथ हमने ऊर्जा विभाग के काम का review किया, कुछ पहलुवों पर अच्छे से विचार-विमर्श हुआ जिसमें एक प्रमुख जो ध्यान में आया कि कुछ power plants पश्चिम बंगाल में बहुत पुराने हैं और पर्यावरण, environment के लिए भी काफी घातक हैं, कुछ plants तो 30-30 साल पुराने हो चुके हैं जिसमें specific coal consumption भी बहुत ज्यादा होती है, कोयले का भी इस्तेमाल ज्यादा होने से पर्यावरण के ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो मैंने एक सुझाव दिया है जिसपे पश्चिम बंगाल की सरकार को निर्णय लेना होगा, कि KTPS जहाँ पे 1260 MW की क्षमता के plants चल रहे हैं कोयले के plants उसको 2 phases में अगर super-critical plants के साथ replace किया जाए और दूसरा एक PTPS जहाँ पे 455 MW की क्षमता के अभी power plants चल रहे हैं उसको भी एक super-critical plant से replace किया जाए, ऐसे इन 2 प्लांट्स पे अगर शुरुआत में focus करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बिजली का खर्चा भी कम होगा, कोयले का खर्चा कम होगा, कोयले का consumption कम होने से पर्यावरण के ऊपर भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा, ऐसे विषय पे काफी सार्थक चर्चा हुई है जिसपे अब पश्चिम बंगाल की सरकार उचित निर्णय जल्दी लेगी |

कोयले के 6 block आवंटित किए थे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लेकिन कुछ court case की वजह से उसको पुनः एक बार शुरू करने में थोडा विलंभ हुआ, लेकिन मुझे ख़ुशी है कि आज जब मुझे बताया गया कि court cases समाप्त हो गए हैं और अब जल्द ही reverse bidding के द्वारा जो नीलामी के द्वारा जो कोयले के MDO का काम, कोयला निकालने का जो काम देने की प्रक्रिया है वो पूरी की गई है और जल्द ही उसके orders issue किए जाएंगे | उसके साथ-साथ ये भी मुझे आज जानकारी मिली कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ये MDO की प्रक्रिया एक निर्धारित की थी जिसमें reverse bidding की प्रक्रिया से price determine होती है वो प्रक्रिया जब राज्य सरकार ने की तो उसका लाभ बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, जो Rs 1564 प्रति टन MDO का खर्चा आता था पंच्वाडा नार्थ में जो सबसे बड़ी माइन है जिसमें लगभग 15 million tonne हर साल produce करने की capacity है उस 15 million tonne की mine में जो Rs 1564 प्रति टन दाम था वो घट के 774, that is less than 50% of the original cost. जिसका सीधा-सीधा 1000 करोड़ का लाभ आगे चलके पश्चिम बंगाल को मिलेगा | तो एक बार और जो हमारी नीति है नीलामी की जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोयले के blocks के आवंटन में शुरू की थी उसके बाद उसको हमने MDO में लागू किया आगे चलके कोयले के linkages में भी, power में भी इसको लागू करने जा रहे हैं, non-power में तो already लागू किया है बहुत successfully.

इस सबसे ये ज़ाहिर होता है कि इमानदारी से किया हुआ reverse e-auction का जो प्रक्रिया केंद्र सरकार ने लागू किया है उसका देश को कितना लाभ होगा और जल्द ही हम चाहेंगे कि ये सभी blocks operation में आए | साथ ही साथ कुछ विषय statutory clearances के मेरे सामने रखे गए जिसपे चर्चा की गई है उसमें कुछ राज्य सरकारों और Environment Ministry की भी मदद लगेगी | राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके उन clearances को जल्द से जल्द तेज़ करने की प्रक्रिया करेंगे |

एक और विषय जो आज चर्चा में आया वो था देवचा पंचमी के कोयले का ब्लाक जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहले मेरे से चर्चा की थी, उसमें लगभग 6 कंपनियों को, 6 राज्यों को ये ब्लाक का आवंटन किया गया है, actually 7 राज्यों को, 6 राज्यों को और एक SGVN ऐसे 7 कम्पनियों को ये कोयले का ब्लाक देवचा पंचमी दिया गया है, वैसे विश्व में ये सबसे बड़े ब्लॉक्स में गिना जाता है - 2000 million tonne एक ही ब्लाक में, 2000 million tone, 200 करोड़ टन कोयला एक ही ब्लाक में है तो मैंने प्रक्रिया शुरू की है केंद्र में कि 6-7 कंपनियां एक साथ एक ब्लाक को mining करें उससे कठिनाई बढ़ेगी, JV करना, निर्णय एक साथ करना तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कुछ राज्यों को अगर कोई और ब्लाक दे दिया जाए तो इस ब्लाक की operations को ज्यादा सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं | साथ ही साथ pump storage का काम इस राज्य में चल रहा है, एक pump storage पुरलिया में काम कर रही है दो और पे काम राज्य सरकार कर रही है, सराहनीय काम है | इसके ऊपर केंद्र सरकार विचार कर रही है किस प्रकार से pump storage को भी और सहायता दी जाए, एक छोटी committee बनाने का मैंने सुझाव दिया है राज्य सरकार को जिसमें Secretary Power, West Bengal की अध्यक्षता में CMD Discom, CMD WB, West Bengal PDC (Power Development Corporation) और Director Marketing Coal India और Director Marketing Finance, ये पांचो व्यक्ति बैठके चार हफ्ते के अन्दर हमें एक रिपोर्ट देंगे पूरा study करके कि किस प्रकार से ये जो पश्चिम बंगाल देश से अलग 25% cess लगाता है जबकि पूरे देश में 14% royalty लगती है, उसका प्रदेश में क्या फायदा हो रहा है और उसके सामने प्रदेश को क्या नुक्सान हो रहा है इसके बारे में खुले दिल से, खुले मन से ये committee चर्चा करके study करेगी | मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर जैसे पूरे देश में 14% royalty लगती है वो अगर West Bengal में भी लगे तो कोयले का उत्पादन यहाँ और बढ़ सकता है, कोयले का उत्पादन बढ़ने से overall revenue state का कम नहीं होगा उलटे बढेगा लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर नौकरियों का अवसर बढ़ सकेगा, ancillary industry आएगी, बाकी पॉवर का कास्ट कम हो सकेगा क्यूंकि आखिर ये लोड पॉवर पे, सीमेंट पे जो जो इंडस्ट्रीया चलतीं है उसपे लोड होता है, तो अगर उत्पादन बढ़ता है तो एक तरफ royalty के माध्यम से ज्यादा पैसा आएंगे दूसरी तरफ industry को और power को फायदा पहुँचने से यहाँ नए jobs का निर्माण होगा, रोज़गार बनेंगे, बिजली का खर्चा कम होगा और सबसे बड़ा लाभ होगा जो District Mineral Fund, अब मेरे पास खनन मंत्रालय, Mines Ministry भी आ गई है तो उसमें हमने

जो District Mineral Fund की कल्पना रखी है, 30% royalty का, local area development के लिए लगता है तो वो लाभ भी पश्चिम बंगाल के लोगों को मिल सकेगा, तो ऐसे एक holistic view ये committee लेके 4 हफ्ते में रिपोर्ट देगी फिर राज्य सरकार इसपर विचार करेगी | इस प्रकार से आज बहुत ही सार्थक चर्चा ऊर्जा मंत्री जी और मनीष दा के साथ हुई है | आखिर में मैं सिर्फ एक बात और बताना चाहूँगा जोकि मेरे मंत्रालय से हटके बात है; Organ Donation Day, 13th August को अभी-अभी मनाया गया, तब मैंने appeal की थी मेरे सभी विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को कि ये एक देशहित का काम है उसके बारे में थोडा विचार करें तो मुझे अभी-अभी Chairman Coal India ने सिर्फ Coal India के headquarters की 112 लोगों की सूची मुझे दी है जिन्होंने Organ donation का निर्णय लिया है और मैं बधाई दूंगा इन सभी को जिन्होंने Organ donation का निर्णय लिया | मैं समझता हूँ इस देश की इतनी बड़ी जनसँख्या में आज भी लोगों को organs नहीं होने के कारण से ज़िन्दगी गंवानी पड़ती है जब कई बार अगर Organ available होते तो लोगों की ज़िन्दगी बच सकती थी | कुछ आंकड़े थे कि 2-2.15 लाख लोगों की ज़िन्दगी हर वर्ष बच सकती है, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा देश भक्ति का काम है इन सभी 112 कर्मचारी और उनके परिवारजनो को मैं बधाई दूंगा और मुझे बताया गया कि और भी बहुत उत्साह है सभी ऊर्जा और कोयला और खनन क्षेत्र के कर्मचारियों में कि वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, आप सबके माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि सभी लोग इस विषय में अपना ध्यान आकर्षित करें |

बहुत बहुत धन्यवाद !

Q&A

सर एक सवाल है, यूपी में नगला फतेला गाँव में आपका views थोडा जानना चाहेंगे?

ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है कि जो राज्य सरकार हमें details देती है, आंकड़े देती है जिसको हम पूरा transparently जनता के समक्ष रखते हैं और उसके बेसिस पे जब हम घोषित करते हैं किसी गाँव को विद्युतीकरण हो गया है उसके बाद भी किसी प्रकार की controversy होना मेरे लिए बहुत ही surprise और बहुत ही, मैं कहता हूँ एक प्रकार से दुःख होता है क्यूंकि ये संघीय ढांचा है अगर मुझे ऊर्जा मंत्री पश्चिम बंगाल कुछ बताते हैं कि इस गाँव का विद्युतीकरण हो गया, इस गाँव में हमने intensive electrification कर लिया, इतने गरीबों के घर में बिजली दे दी तो स्वाभाविक है मैं इनपे पूर्ण विश्वास करूँगा | संघीय ढांचे में किसी को कोई अधिकार नहीं है केंद्र में कि राज्य सरकार हमें लिखके दे और हम उसको disbelieve करें | उसके साथ-साथ मैंने पूरी details दीं कैसे राज्य सरकार ने हमको लिखित रूप से दिया 2013 में केंद्र सरकार को कि इस गाँव में शून्य घर में बिजली पहुंची हैं, मेरे पास यहाँ दस्तावेज़

हैं अगर आपकी इच्छा हो देखने की तो देख सकते हैं, कि राज्य सरकार की Chief Secretary-level committee ने हमें लिख के दिया कि नगला फटेला में 2013 में, एक भी गाँव में नगला फटेला के गाँव में एक भी घर में बिजली नहीं है और इसमें हमें बिजली पहुँचाने की आवश्यकता है, अब अगर आपका कैमरा इस शीट पे ध्यान दे, तो ये नगला फटेला की रिपोर्ट है 2013 में हमें राज्य सरकार से मिली है इसमें दिया है - Coverage of Households – 0,0,0,0,0 और शायद कुछ 9 या 4 घर में बिजली ऐसा कुछ लिखा है, नहीं वो भी proposed to be electrified है, sorry ! No. of BPL households – 0, electrified on date – 0, number of SCR households – 0, तो इस प्रकार की हमें शून्य infrastructure की रिपोर्ट दी |

Existing infrastructure, Nagla Fatela, ये existing infrastructure – 0,0,0,0, ये राज्य सरकार की रिपोर्ट है अब कल मैं किसी चैनल पे देख रहा था मुझे लगता है, ETV है क्या इधर? ETV है? ETV पे मैं कल देख रहा था, सनसनी खबर आप बता रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी आपकी सनसनी खबर पे क्यूंकि सनसनी खबर ये थी कि वहां के मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे कि 1985 से वहां पर काम चल रहा है और अगर 1985 से काम चलने के बाद शून्य infrastructure create हुआ था तो मुझे लगता है कि 28 वर्ष तक क्या हो रहा था मुझे समझ में नहीं आया | और राज्य सरकार ने फिर हमें लिखके भेजा कि इसको energise हमने कर दिया है 30 October को हमें रिपोर्ट भेजी जिसमें हाथरस के नगला फटेला में ये सेन्सस कोड में 'were completed' ऐसा लिखके 30 October को भेजा हमने उसको विश्वास किया, उसके बाद हमें एक Energisation Report भेजी गई जो पश्चिम बंगाल से भी आती है और जब पश्चिम बंगाल से भी आती है हम उसपे वही विश्वास करते हैं | ये उत्तर प्रदेश से 24 November, 2015 की, 24 November, 2015 की रिपोर्ट आई कि ये infrastructure create हुआ है ये लाइन लगी है और 1,2,3,4,5 अधिकारियों ने sign किए हैं, पूरी लाइन एक नहीं पूरी डिटेल्ड एक-एक घर में कैसे बिजली जाती है, अब हम इसके बाद अगर अविश्वास करें तो ये संघीय ढांचे का बहुत बड़ा अपमान होगा और अगर हम विश्वास करें तो फिर पता चलता है कि 24 November को बिजली की infrastructure create हुई उसके बेसिस पे क्लेम हुआ, दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत क्लेम किया गया कि काम हो गया और हमें बिजली दी जाए और उसके बाद पता चलता है कि 15 August तक, यानी लगभग 9 महीने तक बिजली नहीं मिली वहां के लोगों को, Energise होने के बाद ये तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और मैं समझता हूँ नगला फटेला का हर एक व्यक्ति धन्यवाद देगा कि प्रधानमंत्री ने इस विषय को पूरे देश और दुनिया के समक्ष रखा |

हमें अभी जानकारी मिली है कि 15 August को जैसे ही प्रधानमंत्री जी का भाषण ख़तम हुआ उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारी वहां पहुंचे और तुरंत Energise पुनः एक बार करके लोगों के घर में बिजली दी, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई controversy नहीं है, open and shut case है, हमारे अधिकारियों ने उनको showcause जो दिया या showcause नहीं बोलूँगा clarification मांगी उसका

एक बहुत ही कमज़ोर जवाब हमारे पास आया है , उस जवाब से साफ़ ज़ाहिर होता है कि राज्य सरकार समझ नहीं पा रही है कि वो क्या बोलें, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं '85 से बिजली का काम हुआ, अभी मैंने आप के ही टीवी चैनल पे देखा ETV से अगर आप हैं और राज्य सरकार हमको, उन्ही की राज्य सरकार लिखके दे रही है कि काम हुआ नहीं है हमें पैसे दो तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसके ऊपर मुझे लगता है उचित कारवाई करने की आवश्यकता है |

सर DVC के लिए, .. छोड़ने से बहुत प्रॉब्लम होता है और ये एक controversy बन गया है state और centre के बीच मैं, इस पर आप क्या बोलेंगे?

देखिये कोई controversy नहीं हुई है centre और state के बीच में, डैम का पानी छोड़ना है क्या ये निर्णय DVC नहीं करता है, मैं स्पष्ट करदूं आप सभी के माध्यम से, पानी क्या छोड़ना है ये निर्णय DVC नहीं करता है एक अथॉरिटी है उस अथॉरिटी में राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि हैं और वो अथॉरिटी उस डैम की स्टोरेज कैपेसिटी और उसकी सेफ्टी को कंसीडर करके ये निर्णय लेता है, तो इसमें DVC का कोई निर्णय में Veto या निर्णय लेने का final word DVC के पास नहीं है वो उस अथॉरिटी के पास है |

पर ये पानी छोड़ने से तो हर बार ये situation होता है इसका कोई remedy, आप की तरफ से कोई सोच है?

अभी तक इसपर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है पर अगर राज्य सरकार उचित समझे तो मैं Central Water Resources जो department है, CEA और राज्य सरकार, तीनों को मिलके बैठ सकते हैं और वो लोग इस पर पुनः एक बार विचार करें कि इसके बारे में long term view क्या लेना चाहिए | तो I think Manish da we can do that? (हाँ, Of course)

(Minister, Bengal) Our Chief Minister is asking for that, the central government what are the body, whatever is there is responsible for water releasing, they should talk to the government and after discussion they can release the water or otherwise ….

ऐसा करते हैं कि, अभी अच्छा आपने point flagg-off किया, हम CWC, water resources की जो body है, CEA और राज्य सरकार, तीनों एक बार इस पूरी प्रक्रिया को समझ लें, जांच लें और अगर आपके अधिकारी अगले हफ्ते ही आ जाएं तो अगले हफ्ते ही हम बैठके इसको तीनों centre और state इस पर एक पुनः विचार कर लें कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी तक चल रही है और आगे इसमें कुछ सुधार होना चाहिए |

(Minister, Bengal) Whatever honorable Minister has said, I will communicate to my Chief Minister and accordingly.